people without waiting for requisition or permission from any Government.

On behalf of flood affected people of Adilabad District and other affected districts, I request the Government of India to send teams to all the flood affected States to help the affected people by taking all necessary measures.

(xii) Need for immediate flood relief operation in Karimnagar (Andhra Pradesh)

SHRI M. SATYANARAYANA RAO (Karimnagar) : There was unprecedented heavy rain and flood in my Parliamentary constituency and District Karimnagar in Andhra Pradesh on 9th, 10th and IIth of August. Due to this, there was substantial loss of human life and damage to public and private property. Nearly fifty thousand families were rendered homeless and about fifty lives were lost due to drowning and house collapse in the wake of floods. This was the first time in the history of Karimnagar district that such a colossal loss occurred. About two thousand cattle were washed away and over ten thousand sheep and other live stock perished in floods. Almost all the irrigation tanks were either breached and Panchayat Samithi and Zila Parishad roads were completely damaged. About fifteen thousand houses were completely destroyed and about 20 thousand houses were partially destroyed. About fifty thousand acres of wet and two lakh acres of dry crops were completely damaged. About one thousand oil engines and pump sets along with meters were washed away and the wells were completely silted up. All loss put together is estimated to be fifty crore rupees.

Relief operations in area affected by floods should be undertaken immediately. Particularly food supplies should be sent to marooned areas. Adequate financial assistance should be given by the Central Government for relief operations. Central teams should be sent to the flood affected areas in the districts to assess the losses caused to the crops and other properties.

(xiii) Need for ensuring full implementation of the Agrarian Reforms Laws

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani) : There is a steady setback on the issue of Agrarian Reforms. Land ceiling laws are not being seriously implemented even in centrally administered States and Union Territories. Worse is the case with the implementation of tenancy laws. Community laws are being encroached upon by the rural rich. Provisions of money-lending laws are being violated in every village and town of the country with regard to the rates of interest, etc. Debt cancellation laws are simply on paper. The Bihar Land Reforms (Amendment) Bill, 1982, seeking to restore intermediary (Zamindari) rights to the Tatas is awaiting the President's assent which will turn thousands of house, land and factory owners of Jamshedpur into sub-tenants of the Tatas with retrospective effect since 1950. I do hereby draw the attention of the Government to ensure refusal of the President's assent to this Bill and ensure full implementation of agrarian reforms.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House stands adjourned lill 2.20 P.M.

13.25 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till twentyfive minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at thirtyone minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*]

COPYRIGHT (AMENDMENT) BILL—*CONTD.*

MR CHAIRMAN : We will now take up further consideration of the motion to amend the Copyright Act, 1957.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं कापीराइट (एमेंडमेंट) बिल, 1957 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदया जो यह बिल लाई हैं,

यह एक प्रशंसनीय कार्य इन्होंने किया है हालांकि इसमें देरी बहुत हुई है। सन् 1971 में जब इसके सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया था कि इस प्रकार का बिल जल्दी लाया जाए, जिसमें लेखकों और साहित्यकारों का जो शोषण हो रहा है, उससे उनको बचाया जाए, तो यह बिल जल्दी आना चाहिए था लेकिन देरी से आने के बाद इसमें जो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, उससे उनको काफी राहत मिलेगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल हमारे देश में जिस प्रकार से कला-कृतियों, चित्रों और मूर्तियों तथा अन्य प्रकार की दूसरी ऐसी चीजों को चोरी करके विदेशों में भेजा जा रहा है, इस बिल में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे देश की प्राचीन कला-कृतियों को इस प्रकार से खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो हमारी संस्कृति को बहुत क्षति पहुंचा रहे हैं, उनको बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। आपने सुना होगा कि हमारे राजस्थान में जितने राजा-महाराजा हुए हैं, उनके पास बहुत पुरानी कला-कृतियां इस प्रकार की हैं, उनके पास किताबें भी हैं धार्मिक किताबें भी हैं और अन्य प्रकार की पुराने लेखकों की पांडुलिपियां भी वहां पर उपलब्ध हैं।

इस प्रकार की पुरानी कला-कृतियों को जो हमारी संस्कृति के विरोधी लोग है और ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत खराब है, वे ही इस सारी व्यवस्था में गड़बड पैदा करने में लगे हुए हैं। कुछ वर्ष पहले हमारे यहां बहुत कीमती मूर्तियों को विदेशों में बेचा गया था और उनके सम्बन्ध में कहीं पर पता नहीं चला कि उनको कहां पर बेचा गया। हमारे जो मन्दिर हैं, उनमें लाखों-करोड़ों रुपये की पुरानी कला-कृतियां हैं और हमारे देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं, जोकि अष्ठ-धातु की बनी हुई हैं और जिनकी कीमत अपार है। इस प्रकार की कला-कृतियों को लोग विदेशों में ले जाकर बेच देते हैं। मेरी समझ में इस प्रकार की कोई माकूल व्यवस्था इस कानून के अन्दर होनी चाहिए थी मगर इस सम्बन्ध में कोई भी लाज इसमें नहीं रखा गया है, जिससे इन चीज़ों को रोका जा सके। ऐसी व्यवस्था निश्चित तरीके से होनी चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यहां पर बहुत से गिरोह बने हुए हैं जैसे कि स्मगलिंग करने वालों का एक गिरोह है। इसी प्रकार से इन कला-कृतियों की चोरी करने वाला भी एक गिरोह है जोकि हमारे यहां की सभ्यता, संस्कृति और कला-कृतियों को चुराता है और चुराकर विदेशों में बेचता है। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई प्रावधान मंत्री महोदया ने इस बिल में नहीं किया है, जिससे हमारी जो संस्कृति नष्ट हो रही है, जो हमारी पुरानी सभ्यता नष्ट हो रही है, वह नष्ट होने से बच सके और हमारी जो आगे वाली सन्तान है उसको कैसे इस का पता चलेगा कि हिन्दुस्तान में इस प्रकार की भव्य संस्कृति किसी समय थी। इसके सम्बबन्ध में बच्चों को जानकारी मिले। इन सारी चीज़ों को लोग-बाग खत्म कर रहे हैं जिनके सम्बन्ध में आपने किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब भी समय है। अगर इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया तो हमारी ऐसी चीजें और कलाकृतियां जो कि बच गई हैं वे भी नहीं बच सकेंगी।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : यह तो आरकेलोजिकल सर्वे आफ इंडिया करता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : वह क्या करता है, इसको हम सब जानते हैं। हमने उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मन्दिर को देखा है। उसकी वह मेंटीनेंस कैसे कर रहा है, यह हमें उसे देखकर पता लगा। वहां की तमाम मूर्तियां नष्ट होती जा रही है। आपका डिपार्टमेंट उनको मेंटेन करने का काम नहीं कर रहा है।

श्रीमती शीला कौल : मैंने भी उसे देखा है। It is in very good condition, Sir, and well maintained.

श्री गिरधारी लाल व्यास : एस्टीमेट्स कमेटी ने भी उसे देखा है। भुवनेश्वर में भी मन्दिर हैं, उनको भी हमने देखा है और यह भी देखा है कि आपका आरकेलोजिकल डिपार्टमेंट उन्हें कैसे मेन्टेन कर रहा है।

MR. CHAIRMAN : Mr. Vyas has looked with different eyes.

श्री गिरधारी लाल व्यास : पुरी में जगन्नाथ जी का सबसे प्राचीन मन्दिर है और हिन्दुओं का वह सबसे पवित्र मन्दिर है। उसकी क्या व्यवस्था आपका डिपार्टमेंट कर रहा है ?

MR. CHAIRMAN : Mr. Vyas, this is a Bill to amend the Copyright Act. Please come to the Bill.

श्री गिरधारी लाल व्यास : ये उस डिपार्टमेंट की भी मिनिस्टर हैं। इन्हें चाहिए कि ये उसकी भी उचित व्यवस्था करें। वहां पर अच्छी व्यवस्था नहीं है।

इस कापीराईट के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग या मेडिकल की किताबें जो विदेशों के लेखक लिख रहे हैं और जो कि यहां छपती हैं वे बहुत ज्यादा दामों में यहाँ बिकती हैं। दो-दो सौ रुपये की एक किताब आती है। उन किताबों को गरीब बच्चा तो खरीद नहीं सकता है। आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि गरीब बच्चे भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की किताबें खरीद सकें और वे सस्ते दामों पर सभी को उपलब्ध हों। आप उनको सब्सीडाइज्ड करें ताकि सभी गरीब बच्चे खरीद सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें।

पुस्तकों का जो अनुवाद किया जाता है, उसमें भी काफी गड़बड़ी होती है। यहां के प्रकाशक लोग उसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं और जिसको करने का उनको अधिकार नहीं है उसको भी वे करके पुस्तकें छाप देते हैं। इसलिए बहुत सारी उल्टी-सीधी किताबें आपको देखने को मिलेंगी। जिस तरह की अनुवाद की हुई पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिएं वे नहीं हो रही हैं। इस सम्बन्ध में भी आप कुछ न कुछ उचित व्यवस्था कीजिए।

आप फिल्मस की बात को ले लीजिए। वीडो की जो फिल्मस आती हैं उनकी कैसी चोरी हो रही है। गन्दी से गन्दी फिल्म चोरी से यहां लाई जाती है। वे फिल्में यहां न आ सकें इसकी भी कानून में व्यवस्था कीजिए। ऐसी भी व्यवस्था कीजिए जिससे कि गन्दे से गन्दा साहित्य यहां न आ सके। उसकी भी व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। जो लोग इस प्रकार का गलत काम करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इसकी भी कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

प्रकाशक और लेखक के बीच जो टसल है, उसके लिए आपने एक बोर्ड बना दिया है। लेकिन क्या एक बोर्ड सारी व्यवस्था ठीक कर सकेगा ? एक लेखक आदमी अपनी लेखनी के जरिये से जीविका चलता है, वह बड़े प्रकाशक के हाथ में पड़ जाता है।

प्रकाशक लेखकों का शोषण करते हैं, सारा धन स्वयं डकार जाते हैं, लेखकों को जितना मिलना चाहिए नहीं मिलता है। इस चीज को रोकने के लिए आपने क्या उपाय किया है, यह भी आपको देखना चाहिए था।

कुछ राजनीतिक दल हैं जो कम्युनल भावनाएं फैलाते हैं, उस प्रकार के साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं। यह देश के लिए बहुत घातक है। उस प्रकार के साहित्य को, किताबों के प्रकाशक को आप किस प्रकार रोकने जा रहे हैं, उसके लिए आपने क्या प्रावधान किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। सांप्रदायिक भावनाएं फैलाने वाले लोग, गलत तसवीर पेश करने वाले लोग जो हमारे देश के सम्मान के खिलाफ बातें किसी भी किताब में लिखते हैं, इस चीज को रोकने के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, यह भी आप हमें बताएं।

बिल बहुत बढ़िया है। कुछ कदम तो आपने आगे बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं है। अन्य बातें जो रह गई हैं जिनके लिए आपको और कदम

उठाने चाहिएं, उनके बारे में आपने क्या निश्चय किया है, यह भी आप हमें बताएं।

सभापति महोदय, आपकी स्टेट की एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। वहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। जिस तरीके से सारी किताबों को, पाठ्यक्रमों को वह पलटने की कोशिश कर रही है, सारे साहित्य को शिक्षा के क्षेत्र में तबदील करने की कोशिश कर रही है, टैगोर जैसे लोगों की कलाकृतियों को नष्ट करने की कोशिश कर रही है और उसके स्थान पर अपना साहित्य लाने की कोशिश कर रही है, क्या उससे हमारी संस्कृति बचेगी, यह भी आपको सोचना चाहिए और इसके बारे में भी आपको कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। बंगाल में बहुत गड़बड़ी इस प्रकार की हो रही है। इस सम्बन्ध में भी आपको कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए था ताकि पुरानी जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारी संस्कृति के जो स्तम्भ हैं, टैगोर जैसों की कलाकृतियां हैं, वे नष्ट न हों, हमारी सभ्यता नष्ट न हो, हमारी संस्कृति नष्ट न हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। इसको बारह साल के बाद लाया गया है। अन्तराष्ट्रीय समझौते होते हैं और उन समझौतों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मित्र देश आपस में अनुबन्ध करते है। कलाकारों, साहित्यकारों, नाट्यकारों या संगीतकारों द्वारा जो साहित्य सृजन किया जाता है, जिन कृतियों का सृजन किया जाता है, उनके बारे में जितना प्रावधान इस विधेयक में आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया है। यह इसमें कमी है। आपको एक व्यापक विधेयक ले कर आना चाहिए था।

बान कनवैंशन 1947 में हुआ था। उसका उद्देश्य था प्रोटैक्शन आफ लिट्रेसी एंड आर्टिसटिक वर्क्स। फिर उसके बाद 1952 में ब्रसल्ज कनवैंशन हुआ, यूनिवर्सल कापीराइट कनवैंशन। उसके बाद हमारे देश में 1957 में कानून बना। यह चार पांच बरस बाद बना। उसी परम्परा को निभाते हुए बारह बरस के बाद पैरिस कनवैंशन हुआ और उस कनवैंशन में इस बात को स्वीकार किया गया कि अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में मित्र देशों में एक दूसरे देश के साहित्य का आदान प्रदान होना चाहिए, विश्वविद्यालयों के लिए महाविद्यालयों के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए किताबों की जो जरूरत होती है उसको पूरा किया जाना चाहिए। यह सही बात है कि विकासशील देशों को विकसित देशों की जो प्रोद्योगिकी सम्बन्धी पुस्तकें होती हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है।

वैज्ञानिक पुस्तकें हैं, साहित्य संम्बन्धी पुस्तकें हैं और ग्रन्थ है उनका अनुवाद अनिवार्य हो जाता है और भाषान्तर करके फिर पुर्नउत्पादित करने के लिए प्रावधान है। मंत्री जी ने जो प्रावधान किया है इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ विदेशी साहित्यकारों को ही होगा। लेकिन भारतीय साहित्यकारों, संगीतकारों, नाट्यकारों या अन्य कलाकृतियों के निर्माताओं का जो भयंकर शोषण हो रहा है उसको रोकने का प्रावधान नहीं है। इसमें इसकी व्यवस्था करनी चहिए थी, जो नहीं है।

औचित्यपूर्ण रायल्टी का प्रावधान भी नहीं है। तीसरे ऐसी पुस्तकों के व्यापक बिक्री हेतु समाज की वर्तमान क्रयशक्ति के अनुसार सस्ता साहित्य प्रकाशित कराकर, अनुदित कराकर, अन्तर्राज्यीय साधनाओं में लगे चिन्तकों, सृजकों एवं संगीत रचनाकारों की जीविका चलाने की व्यवस्था का भी कोई प्रावधान नहीं है। अश्लील एवं भोंडे साहित्य, उपन्यास, नग्नताजन्य कलाकृतियों पर पाबन्दी लगाने की व्यवस्था नहीं है। सत्साहित्यों के मुद्रणालय में भाषान्तर करने, पुनरुत्पादन करने की दिशा में तथा मुद्रित प्रतियों की संख्या के प्रतिवेदन प्राप्त करने तथा उचित रायल्टी साहित्य सृजकों को दिलाने का प्रबन्ध नहीं है। कापी राइट बोर्ड को किताबों के मूल्य निर्धारण करने की औचित्यता पर विचारार्थ सक्षम नहीं बनाया गया जिससे मनमाने ढंग से लागत का

अत्यधिक मूल्यांकन कर के सरकारी पुस्तकालयों, संस्थाओं का पोषण करने की प्रवृति बढ़ी है। साधारण आदमी किताबें नहीं खरीद सकता। इसलिये ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें समाज के अधिक लोगों के लिये लाभप्रद सिद्ध नहीं हो पाती क्योंकि मूल्य इतना अधिक रखते हैं और प्रकाशकों और अन्य संबंधित अधिकारियों में तालमेल रहता है जिस कारण से केवल सरकारी पुस्तकालयों में ही वह किताबें रहती हैं। अतः मूल्य निर्धारण का भी इसमें प्रावधान होना चाहिये, जो कि अभी नहीं है।

भारतीय संस्कृति, कला, वेद वेदान्त, शास्त्र, गीता आदि भारतीय धरोहरों के अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में भाषान्तर करने वाले प्रकाशकों से रायल्टी लेने वाले की व्यवस्था नहीं है। ऐसे साहित्य के लिये अगर देश के अन्दर साहित्य और संस्कृति निधि कर रखा जाय तथा उसके द्वारा जो रायल्टी मिले वह उस निधि को मिलनी चाहिये जिससे राष्ट्रीय संस्कृति और कला निधि के रूप में उसका विकास हो सके और साहित्य का सृजन हो सके। इसका प्रावधान होना चाहिये था, लेकिन वह भी नहीं है।

जो टाइम की पाबन्दी लगा दी गई है, यों तो कई मित्रों ने कहा 1 महीना रखना चाहिये क्योंकि जमाना प्रगतिशील है; लेकिन मेरा कहना है कि जो साहित्य है, वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किया है वह शास्वत है, उसके लिये 2,3 वर्ष क्या वह तो पचासों साल तक चल सकता है। 5 या 10 वर्षों के उपरान्त लेखकों या साहित्यकारों, कलाकारों को सक्षम बनाने के लिये और यदि उनके साथ धोखाधड़ी का काम कोई प्रकाशक करता है तो वह दूसरे प्रकाशक को दे कर अधिक रायल्टी प्राप्त कर सकें ऐसा प्रावधान इस बिल में नहीं किया गया है, जिसका होना नितान्त आवश्यक है। अभी प्रकाशक क्या करते हैं कि 50,000 प्रतियां छापते हैं तो 5,000 ही बताते हैं।

इस तरह की धोखा-धड़ी करने वाले प्रकाशकों से लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों को बचाने के लिए पांच या दस बरस के बाद उन्हें फिर से कापीराइट मिल जाना चाहिए, ताकि वे अपनी कृति को किसी अन्य प्रकाशक को देकर अधिक रायल्टी प्राप्त कर सकें और पुन. संशोधित संस्करण छपवा कर फायदा उठा सकें।

गुमनाम साहित्यकारों के नाम से लाखों पुस्तकें छपती हैं। उन्हें लिखने वाले बहुत गरीब और निर्धन साहित्यकार होते हैं। उनकी रायल्टी को हज्म करने के लिए और उनका शोषण करने की मंशा से प्रकाशक दो चार हजार रुपए देकर उनकी कृतियों का कापीराइट ले लेते हैं और उन्हें दूसरे नामों से, या बोगस नामों से, प्रकाशित करते हैं। इस बारे में भी इस बिल में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

चोरी लेखन करने वाले प्रकाशकों, नकलची लेखकों और मूल विचार को तोड़-मरोड़ कर पाठकों तथा जनता के सामने रखने वालों की आपराधिक कार्यवाहियों को संज्ञेय अपराध घोषित करने की भी इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं है।

फोटो-कैसेट, फोटो-फिल्मिग और माइक्रो-फिल्मिग के माध्यम से आज अवैध रूप से कैसेट-निर्माण और उनकी तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। यहां पर संगीत का रिकार्ड मार्केट में आने से पहले और फिल्म के प्रदर्शन से पहले ही हांगकांग, जापान आदि देशों में उनकी कापियां मिल जाती हैं, जिसके कारण राइटर या निर्माता का लाभ नहीं होता। सरकार ने इस बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं की है।

इस बिल में यह भी नहीं बताया गया है कि किन किन भाषाओं और किन-किन देशों के साहित्य पर प्रतिलिप्याधिकार कानून, कापीराइट एक्ट, लागू होगा।

इस विधेयक में बहुत सी कमियां हैं, जिनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। फिर भी इसे ठीक दिशा में एक कदम कहा जा सकता

है। 1957 में जो एक्ट बना, उसमें बहुत सी प्रशासकीय कमियां रह गई थीं। उन कमियों को दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया है, लेकिन इसे एक व्यापक और सर्वांगपूर्ण संशोधन नहीं कहा जा सकता। इससे लेखकों के हितों और जनहित की सुरक्षा की मंशा की पूर्ति नहीं होती है। इस दिशा में और कदम उठाने होंगे।

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla) : Mr. Chairman, Sir, at the very outset, I must say that to bring forward this Bill is a very progressive step. As India was already committed at the Paris Conference and earlier also at the Universal Rights Convention at Geneva, I feel, it is a progressive step although a belated one. Particularly, I feel that the system of compulsory licence will certainly ensure that we will get good reading materials, translations and also original materials from abroad.

There is a hue and cry from certain publishing houses that it will hit Indian authors. But I feel that the quality of our production will improve and maybe that it will reduce the prices also because of competition. It is not necessary that the books that we import will be costlier.

Then, the institution of a copyright Board is a very important provision in the Bill. It will definitely ensure fair dispensation for authors. But it could be a comprehensive one.

I do not know whether it will meet the requirements. Authors have always suffered in this country and many of my colleagues have already spoken about this. I don't want to repeat. One or two provisions in this Bill could make the institution of this Copyright Board purposeful. For instance, there is no harm for the press and the printers to directly inform the author about the size of the printing order. That will ensure a particular amount of money that is required to be paid to the author. There is no harm in that. I do not know why it has not been indicated.

The publishers' enterprises are auditable. A copy of the audit report must be made available to the author. But the author at present is always in the dark. Whatever the gains of the project 99 per cent goes to the publishing house. 1 per cent may—I do not know whether I am correct to say—goes to authors. Authors do not get their due. But these two measures could certainly ensure proper payment to them. They must know the size of the print order and whenever there is audit, a copy of the audit report must go to them.

The Bill does not provide measures for piracy and the piracy in modern times has different forms like phonographic piracy, casette piracy and there is no provision in the Bill to check piracy and particularly in our neighbouring countries, there is large-scale piracy of the books produced in India and recently the Secretary-General of the Authors Guild has said that publishing houses in Pakistan indulge in large-scale piracy of the books produced in India. There is no provision in the Bill to check this.

I would also suggest that the books giving the gist or the notes—we call them Khulasa in Urdu—for the books produced by institutions like NCERT should also be bracketed under piracy. I have some knowledge of how fake authors and fake publishers indulge in producing these refresher course books and gist of the books produced by NCERT. The result is that students are not allowed to go through the original texts and they read 'one day series' and that affects the standard of learning in the country. I would suggest that so far as piracy is concerned, not only the actual piracy done through films, casettes etc., but production of 'one day series' or the gists of books, what is known in Hindustani, Khulasa, must be brought under the purview of the Bill and bracketed with the forms of piracy indulged in by various people because this kind of piracy adversely affects the standards of learning in the country.

Coming to page 5 of the Bill, I would seek a clarification from the Hon. Minister. While through licences we get literary works on drama etc., there is a provision "in any language" and general use in India "after a period of seven years from the first publication of the work" or "the translation of any such work which is not an Indian work is required for the purpose of teaching, scholarship or research". In the next proviso,

you say that "provided that where the translation referred to in the preceding proviso is in a language not in general use in any developed country, such application may be made after a period of one year from such publication." Why this concession only in respect of certain developed countries ?

I am afraid the term 'developed country' is not a static term, it is a dynamic term. You may adopt the U.N. definition, but that is not sufficient. For instance, the famous economist, Mr. W.W. Rostow gives five stages of economic growth. You may be developed today and you may not be developed tomorrow. So, instead of saying 'developed countries' you could say Great Britain, America, Russia or any other country. If you say 'developed countries', every time you will have to refer to the chart. I do not think this is correct.

15 hrs.

One more illogical thing that appears to me is this. On the same page, in the last but one paragraph there is a proviso which reads :

> "Provided that nothing in clause (ii) shall apply to the export by Government or any authority under the Government of copies of such translation in a language other than English, French or Spanish to any country if—
>
> (1) such copies are sent to citizens of India residing outside India or to any association of such citizens outside India ;"

When we come to export, we export. That is all. If you qualify it by saying that it will be sent "to citizens of India residing outside India or to any association of such citizens outside India", then anybody will form an association and corrupt practices will be indulged in. We do not say that we export only to citizens of India residing outside India and so on. I do not think it is correct.

Finally, it is the actual implementation of the legislation which is important. Whatever provisions there were under this Copyright Act were not implemented most sincerely. Therefore, whatever provisions are being made in this Bill, those provisions require efficient implementation. I would request the hon. Minister that when she rises to answer—I do not know whether she will like to answer because we speak for the sake of speaking ; even when genuine suggestions are made, I do not know whether these suggestions are accommodated at all—to the points we have raised, she must assure us that there will be proper implementation.

15.03 hrs.

[SHRI N.K. SHEJWALKAR *in the Chair*]

SHRIMATI SHEILA KAUL : Sir, I have listened to the speeches of the hon. Members with a great measure of attention and respect. A remarkable feature of the discussion has been that, while the hon. Members have made several valuable points, they have all welcomed the Copyright Amendment Bill. I am grateful to them for this expression of appreciation. I have had the opportunity of explaining that this Bill has a specific purpose in view. I am conscious, at the same time, of the fact that there is so much that needs to be covered by legislation. Let me assure the hon. Members that all the points they have raised will receive our utmost attention. I am glad that the basic purpose of the Bill has been appreciated. Though belated, the Bill, nevertheless, makes a significant breakthrugh in catching up with the provisions of the latest Paris Act, 1971. This was an imperative requirement and with this we correct certain distortions that could have otherwise crept in our administration of the Copyright law.

The point which I have urged earlier and which has received a wide measure of appreciation concerns the free flow of knowledge from one country to another. I may reiterate that the provision regarding compulsory licencing of foreign books is of far-reaching significance and it will help our country in not only keeping abreast of the latest knowledge but also expanding our frontiers of information and access to the latest that is being said and thought. I must immediately, at this juncture, allay an apprehension in the minds of some hon. Members ; let me clarify that the books to be brought under the compulsory licencing

system would only be those books which are not available in India at a reasonable price.

I would be the last person to say that the Bill comprehends all that the Copyright Bill should. A comprehensive legislation on the subject will naturally take into account post-1971 development. These, as Members have referred to, relate to widespead piracy in books, videos, tapes and phonographic compositions. These, as Members rightly pointed out, have become quite complicated issues in the context of sophistication of technology. We have under consideration a broad profile of legislation that would in due course of time, take care of it. But, as Members would kindly appreciate, this would take some time as any proposed legislation will have to look at not only global implications but a number of issues of the inter-Ministerial kind. I am conscious of the need to bring it about and suggestions made by Members from all sections of the House reinforce our resolve that it has to be done urgently.

Now, there are certain points which are common to all the Member's who have spoken. I would like to mention them separately, one by one. Shri Rup Chand Pal suggested that the present measure was inadequate because it did not protect the authors' rights and that the three year period for compulsory licensing was too long. I might, in this connection, mention that clause 19(a) of the Bill does look after the authors' rights as it gives for the first time an opportunity of a dispute being heard and decided in a summary manner. This is to be done in the Copy Right Board.

As regards three and one year limit stipulated under compulsory licensing, I would bring to the notice of the hon. Members the fact that this is based on the Paris enactment and that we have no options in this regard.

Shri Mool Chand Daga referred to the reasons for the delay in bringing up the Bill as also to the issue of widespread piracy of books and faulty translations, particularly, in regional languages. In this connection, I may mention that the Bill was delayed for various reasons. The Paris Act itself came into force in 1974, the proposed amendment based on these lines, was submitted to the Cabinet in 1976. From 1977 onwards, no substantial progress was made till in 1980 when it was taken up again in right earnest. Some of these delays are unavoidable as they involved a number of Departments and Ministries in discussion. The point of piracy as I had a chance of mentioning is general and is being looked into in terms of vast range of its many implications. Here I would like to add as to how, in my own home, in a room a picture was hung on the wall. Shri Rajnath Sonkar Shastri mentioned about my husband. I am grateful to him for bringing up the name of my late husband. You all know that he was a scientist and he was asked to find out water in the desert of Rajasthan. It was in the year 1948-49 that he discovered underground water resources in Jodhpur in Sundhara area where a big pump was erected with four engineers working on it, pumping out the waters. A photo was taken of my husband showing there with two engineers. After a lapse of 20 years, this photograph still decorates a wall in my house.

This was also put in a Science Magazine, saying that that gentleman, the scientist, had discovered this water and this was the picture of the people working at it. Sir, the work had been done by my husband. The picture was taken by us and the picture and everything is hanging in my room and this thing comes out in the magazine that this work was done by somebody else. So, my husband wrote a letter to the magazine editor and the magazine editor sent that letter to this scientist. The scientist writes to my husband and he says, "Professor Kaul, you are an internationally known figure. What if I share your glory ?" Now, this is the sort of piracy that takes place. So, we are also victims of this piracy.

AN HON. MEMBER : What was the further reaction ?

SHRIMATI SHEILA KAUL : When he says that he wants to shine in the glory of others what can you do ?

The question of faulty translation is itself covered under clause 32(4) proviso (d) which

provides for the Copyright Board taking care of the correctness of the translation before permitting compulsory licensing.

Shri Ram Singh Yadav suggested that any person should not be given licence for compulsory publication and also expressed apprehension about the correctness of translation. As I have said before, the correctness of translation is already taken care of in the procedure prescribed in the Bill. It will be difficult for us to insist that only certain selected languages should be used for translation so long as the correctness of the translations is ensured.

Shri K. Rajan while making several points suggested that the authors should themselves be represented on the Copyright Board. I would point out that the Copyright Board is a Quasi-Judicial body which is to go into disputes between authors and publishers. Naturally, therefore, it has to be an impartial body like any other court of law and it cannot have parties to the disputes as Members.

Shri Harish Rawat mentioned that the Copyright Board should be broad based and that it should meet at regular intervals. He also advocated the need for less costly court procedures. A number of other members also referred to the composition of the Copyright Board. I might mention in this connection that the Board is already fairly broad based. It has nine members and they all have judicial standing. The Chairman is always a serving or retired Judge of the High Court. In the very nature of things the Board is supposed to perform quasi-judicial function. It meets on an average once in two months and its disposal of work is very prompt and substantial.

As regards litigation, the very intention of clause 19(a) is to ensure a summary procedure which is not expensive.

Shri Shastri appeared to have an apprehension that the authors got royalty only after their death. This is not correct because under the Copyright Law royalty becomes payable to the author immediately on publication of his work and remains payable throughout his life and for fifty years after his death to his legal heirs.

Yet, another interesting point made related to royalty, not being paid on books like the *Bhagawat Gita*, the *Ramayana*, the holy *Quran* and other known classics.

The Members are perhaps aware that these works are in the public domain and as such they are part of our rich national heritage. So, no royalty is payable on such works. They belong to the public domain.

Prof. Ajit Kumar Mehta took the opportunity of suggesting that it should be possible for the authors to revoke the agreements if they are found to be harmful to their interests.

I may bring to the notice of the Members that the very intention of Clause 19A is to provide for such safeguards in the event of disputes.

This also meets the point made by Shri Shailani who expressed the view that measures should be taken to stop the exploitation of authors by publishers.

Now, Shri Vyas also spoke about piracy. He has gone. He spoke about antiques, he spoke that they are stolen and taken away. For antiques, the registration for antiques is there. It is known as the Antiques Act. If there is anything which is 100 years old it has to be registered and this Antiques Act looks after those problems. He spoke about the temples and all that. That comes under the Archaeological Survey of India. We have difference of opinion on that. Now, he also mentioned about literature prejudicial to maintenance of communal harmony ; there are other agencies to look after this.

Prof. Saifuddin Soz (J and K) mentioned certain other points. I would like to point out to him that if he goes through the Bill thoroughly when he finds time, he would find that many things have been covered in this Bill. When you go through it in a cooler manner, you will find that we have gone into it very carefully and it will give you a clear idea how authors are protected. Of course I have spoken to you at length about piracy. We are trying to do all these things because we are concerned with the enforcement of the Piracy Act,

Not only we, but the international world is interested in such matters and they are also looking into them as would be done by the Government of India.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to amend the Copyright Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The Motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now we take up clause by clause.

There are no amendments.

The question is :

"That Clauses 2 to 23 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 2 to 23 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : All are 'Ayes' only ; there is no 'No' as far this Bill is concerned.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL) : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill be passed.

Now, Shri Shastri.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए दो एक बातें कहना चाहता हूं। वैसे उन बातों की तरफ और भी माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान दिलाया है। कापीराइट के सिलसिले में विधेयक आप पास कर रहे हैं। इस विधेयक का सहारा लेते हुए मैं आपका ध्यान अपने देश के साहित्यकारों, लेखकों, कवियों और खास तौर से हिन्दी के लेखकों की तरफ दिलाना चाहता हूं और उनकी चर्चा करना चाहता हूं। उन्होंने किताबें बहुत महत्वपूर्ण लिखीं, उपन्यास, कवितायें, कहानियां आदि लिखीं। राष्ट्रीय आंदोलन के जमाने में उन्होंने नौजवानों को आन्दोलन करने वाली चीजें भी लिखीं। लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय रही। पुरानी बातों से हम परिचित हैं। प्रेम चन्द जी ने जैसी किताबें लिखीं, वक्त नहीं है कि उन पर मैं चर्चा कर सकूं। लेकिन वह मरे बहुत ही बुरी हालत में। मैं स्वयं उन दिनों बनारस में काशी विद्यापीठ का छात्र था। दवादारू की भी व्यवस्था ऐसे चोटी के लेखक के लिए नहीं हो सकी। उसी तरह जय शंकर प्रसाद जी थे। राहुल सांस्कृतायन जी को कौन नहीं जानता। सौ से ज्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखीं। सुमित्रा नन्दन पन्त बड़े कवि थे। सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला भी थे। हमारे अपने सूबे में एक लेखक थे बहुत बड़े और उनका नाम था श्री शिव पूजन सहाय जी। इन लेखकों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि किताबें तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण लिखीं, पूरे देश को जगाया, साम्राज्यवाद के खिलाफ भी और जमींदारी प्रथा के खिलाफ भी जगाया, मानवता की रक्षा करने के लिए जगाया लेकिन उनकी अपनी हालत बहुत बुरी रही। अभी भी कुछ जिन्दा लेखक हैं जिनकी हालत अच्छी नहीं है। एक दो का नाम मैं लूंगा। हमारे सूबे में मैथिली के बहुत बड़े लेखक हैं और हिन्दी के भी है नागार्जुन। वह कभी बनारस और कभी कलकत्ता और कभी दिल्ली मारे मारे फिरते हैं। बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखीं लेकिन उनको रायल्टी के पैसे नहीं मिलते। इन लोगों को भी नहीं मिले। प्रकाशक उनसे धनवान हो जाते हैं, उन लेखकों का शोषण करके धनवान हो जाते हैं, मालामाल हो जाते हैं लेकिन उनको रायलटी का पैसा नहीं देते हैं। प्रकाशक तो शोषण उनका करते ही हैं सरकार भी उनकी तरफ समुचित ध्यान नहीं देती है। अभी भी हमारे सूबे के एक लेखक हैं राज्य स्तर पर वह प्रसिद्ध हैं जिनका नाम है लाल धुआं। वह बीमार

हैं। जनरल अस्पताल में पड़े हुए हैं। साहित्यकार सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद होनी चाहिए लेकिन कोई मदद नहीं करता है। लेकिन जो जनता को जगाते हैं, उसमें अच्छाई पैदा करते हैं, ऐसे लेखकों की मैं बात कर रहा हूं। उनकी तरफ न आपका और न हमारा ध्यान जाता है। यशपाल को कौन नहीं जानता। राहुल सांस्कृतायन ने समाजवाद की तरफ मुझ जैसे लोगों को मोड़ा जो कम उम्र के थे, लाखों की संख्या में नौजवानों को आकर्षित किया, उनकी स्थिति क्या रही? आगे जब भी आप कानून बनाएं तो उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए और ऐसे लेखकों की सहायता के लिए, आर्थिक सहायता के लिए सरकार को किसी कोष का निर्माण करना चाहिये। जिसमें से आप उनकी मदद कर सकें। राज्यों में भी इस तरह के कोष बनने चाहियें और शिक्षा मंत्रालय को भी एक ऐसा कोष बनाना चाहिए ताकि उसमें से हम उनकी मदद कर सकें।

दूसरी बात मैं रायलटी के बारे में कहना चाहता हूं। वादा तो लेखकों के साथ इसके बारे में किया जाता है लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता है। रायलटी कम भी दी जाती है जो रायल्टी तय की जाती है वह भी उनको मिलती नहीं हैं। लेखकों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे मुकदमा करके रायलटी का पूरा पैसा ले लें। इंदिरा जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किताबें लिखीं उसकी रायलटी मिल सकती है लेकिन सब लोग तो देश के प्रधान मंत्री नहीं हैं।

श्रीमती शीला कौल : नहीं, उनको भी नहीं मिली शुरू में।

श्री रामावतार शास्त्री : बाद में आपने दिलवायी तो।

श्रीमती शीला कौल : नहीं, मैंने नहीं दिलवायी।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा कहना है कि बड़े बड़े लेखक जो दयनीय स्थिति में हैं उनकी तरफ ध्यान देना सरकार का सबसे बड़ा कर्त्तव्य होना चाहिए, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र की सरकार, और उनको रायल्टी ठीक से मिले, उसका रेट बढ़े। पुस्तकों का मूल्य कम होना चाहिए। हमारा मुल्क गरीब है, पुस्तकों की कीमत साधारण जनता की पहुंच से बाहर है। तो पुस्तकों के मूल्य इतने ऊंचे नहीं होने चाहिएं। अभी तो बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों के लिए महंगी किताबें खरीद भी नहीं सकते क्योंकि 100, 150 रु० की जो किताबें हैं उनको कितने प्रतिशत लोग खरीद सकते हैं? नतीजा यह होता है कि पुस्तकालयों में बच्चे इतनी महंगी किताबों को पढ़ते हैं। इसलिए कीमत की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

हमारे देश में गन्दी पुस्तकें और पत्रिकायें भी छप रही हैं। इनका नियंत्रण होगा या नहीं? या हमारे बच्चों के दिमाग को दूषित किया जायगा? इसकी तरफ भी ध्यान आपका जाना चाहिये।

और आखरी बात जो इससे ताल्लुक नहीं है और जिसके बारे में आपने जवाब भी दिया है, वह है स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। मैं स्वतंत्रता सेनानी हूं, प्रो० रंगा भी हैं और दोनों सदनों में करीब 140 स्वतंत्रता सेनानी हैं, देश में अभी भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जिन्दा हैं, उनके बारे में मैंने सवाल पूछा था, उनका छोटा छोटा जीवन चरित्र किताबों के रूप में छपा दीजिए ताकि आगे आने वाली सन्तान समझे कि हमारे देश के लिए उन्होंने क्या कुरबानी दी।

इन बातों के साथ मैं आपके विधेयक का समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आगे और जो बिल लाइयेगा उसमें इस तरह की तमाम बातों को शामिल कीजियेगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब सदर साहब, अव्वल तो मैं जो बिल सरकार की तरफ से आया है इसकी हिमायत करता हूं और मुबारकवाद देता हूं कि ऐसा बिल आप लायी हैं

जिसके जरिये लेखकों की जो राइटिग्स हैं उनकी हिफाजत के लिये कदम उठा रहे हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो कापी राइट का मसला है, हमारा मुल्क गरीब है अक्सर लोग यहां किताबें नहीं पढ़ते हैं जब कि अमरीका जैसे मुल्क में एक बार कोई एक किताब लिखे तो 10, 50 लाख रु० कमा सकता है। लेकिन हमारे यहां तो यह हालत है कि भले ही उसकी काबलियत हो, बहुत बड़ा लेखक हो लेकिन किताब छपाने के लिये भी उसके पास पैसे नहीं होते और रियासत के जो कल्चरल इदारे हैं, अकादमी हैं, या केन्द्र की जो ऐकेडमीज हैं उनको उसको ऐप्रोच करना पड़ता है कि हमें मदद कीजिए किताब छपाने के लिये। और आप लोगों में किताब पढ़ने का मिजाज पैदा नहीं हुआ है जिसका अंजाम यह होता है कि किताब के छपने में जो उसकी पूंजी लगी है वह भी वापस नहीं आती है। इसलिये इंगलिस्तान या अमरीका के अदीबों के साथ अपने मुल्क के अदीबों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर किताब की कीमत 4 रु० की रखी जाय तो 2 रु० में भी हमारे यहां लोग उसको नहीं खरीदेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि अगर आप अदीबों की हौसला अफजायी करना चाहते हैं तो सिर्फ कापी राइट से यह मसला हल नहीं होगा, हां उसका मैयार देखा जाय, और फिर किताबों की खरीदारी की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। मेरी राय में यह एक जिम्मेदारी बना दी जाय कि चाहे किसी भाषा में हों, इन अदीबों को जो अच्छे लिखने वाले हैं, जिसके ऐप्रोच नहीं है, जो सरकार तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनकी किताबों को लाइब्रेरीज के लिये खरीदा जाय।

अदीबों और लेखकों का खून चूसना और उनकी मेहनत की कमाई पर डाका डालना हिन्दुस्तान के पब्लिशरों का एक धंधा बन चुका है। हिन्दुस्तान की यह ट्रैजेडी है कि अदीब लिखता है और किताब छपती है, लेकिन उसका ज्यादा फायदा पब्लिशर को होता है। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए।

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों में उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी जुबानें रायज हैं और उन दोनों का एक कामन कल्चरल हेरिटेज है। हमने देखा है कि पाकिस्तान के किसी अदीब की उर्दू किताब हिन्दुस्तान में छपती है, मगर उसका रायल्टी देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि चोर पब्लिशर ऐसी किताबों को छापते हैं। इसी तरह हिन्दुस्तान में अदीबों की किताबें पाकिस्तान में छपती हैं, मगर उन्हें रायल्टी में चार पैसे भी नहीं मिल रहे हैं।

इस जिम्न में मैं आपका ध्यान फिल्मी दुनिया की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो कोई अच्छी कहानी या नावल मार्केट में आता है, उसकी चोरी होती है और उसके आधार पर फिल्म बनाई जाती है, लेकिन अदीब इस बड़े भ्रष्टाचार और फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। सरकार का फर्ज है कि वह मुख्तलिफ सतहों पर अदीबों की डिफीकल्टीज को दूर करने की कोशिश करे।

अगर किसी किताब को चोरी से छापा जाता है, तो उस सूरत में सरकार को अदीब को लीगल एड की शक्ल में मदद देनी चाहिए।

हिन्दुस्तान की आजादी की जद्दो-जहद में हिस्सा लेते हुए पिछली पीढ़ी के हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तामिल और तेलुगु वगैरह सब जुबानों के हजारों अदीबों ने बड़ी कुर्बानियां दी थीं, जिसकी तरफ अभी शास्त्री जी ने इशारा किया है। उस वक्त के बहादुर मुजाहिबों ने जो क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाए, उसमें अदीबों और लेखकों का भी बड़ा सहयोग था। यह देखना चाहिए कि किन लेखकों ने 1947 से पहले आजादी के लिए कुर्बानियां दीं और उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए। वे लोग भूखों मर रहे हैं। उनका कोई पुरसाने-हाल नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि खाली कापीराइट से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार वाकई दियानतदाराना तौर पर अदीबों को मदद करना चाहती है, तो जो तरीके मैंने आपके सामने पेश किए हैं, उसे उनके मुताबिक काम करना चाहिए।

کا ایک کامن کلچرل ہیریٹیج ہے۔

ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے کسی ادیب کی اردو کتاب ہندوستان میں چھپتی ہے مگر اس کی رائلٹی دینے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ چور پبلیشر ایسی کتابوں کو چھاپتے ہیں۔ اس طرح ہندوستان کے ادیبوں کی کتابیں پاکستان میں چھپتی ہیں مگر انھیں رائلٹی میں چار پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں۔

اس ضمن میں میں آپ کا دھیان فلمی دنیا کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ جو کوئی اچھی کہانی یا ناول مارکیٹ میں آتی ہے اس کی چوری ہوتی ہے اور اس کے آدھار پر فلم بنائی جاتی ہے لیکن ادیب اس بڑے بھرشٹاچار اور فلم انڈسٹری کی بہت بڑی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سرکار کا فرض ہے کہ وہ مختلف سطحوں پر ادیبوں کی ڈیفیکلٹیز کو دور کرنے کی کوشش کرے۔

اگر کسی کتاب کو چوروی سے چھاپا جاتا ہے تو اس صورت میں سرکار کو ادیب کو لیگل ایڈ کی شکل میں مدد دینی چاہیے۔

ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیتے ہوئے پچھلی پیڑھی کے ہندی اور دوسرے پنجابی بنگلہ تامل اور تیلگو وغیرہ سب زبانوں کے ہزاروں ادیبوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں جس کی طرف ابھی شاستری جی نے اشارہ کیا ہے۔ اس وقت کے بہادر مجاہدوں نے لوکراتنی کاری آندولن چلائے اس میں ادیبوں اور لیکھکوں کا بھی بڑا سہیوگ تھا یہ دیکھنا چاہیے کہ کن لیکھکوں نے ۱۹۴۷ء سے پہلے آزادی کے لیے قربانیاں دیں اور ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے۔ وہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ انکا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔

میں کہنا چاہتا ہوں کہ خالی کاپی رائٹ سے کام نہیں چلے گا۔ اگر سرکار واقعی دیانتدارانہ طور پر ادیبوں کی مدد کرنا چاہتی ہے تو جو طریقے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اسے ان کے مطابق کام کرنا چاہیے۔

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : Mr. Chairman, Sir, I am in favour of the suggestions made by our hon. friends and I am very glad that Ramavatar Shastri Ji, a freedom fighter, has raised this point that the biographies of the freedom fighters in all parts of India in their various struggles

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) جناب صدر۔ اوّل تو جو بل سرکار کی طرف سے آیا ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسا بل آپ لائے ہیں۔ جس کے ذریعہ لیکھکوں کی جو رائٹنگس ہیں ان کی حفاظت کیلئے قدم اٹھا رہے ہیں۔ لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے ہمارا ملک غریب ہے۔ اکثر لوگ یہاں کتابیں نہیں پڑھتے ہیں۔ جبکہ امریکہ جیسے ملک میں ایک بار کوئی ایک کتاب لکھے تو دس۔ پچاس لاکھ روپیہ کما سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ حالت ہے کہ پہلے ہی اس کی تابیت ہو۔ بہت بڑا لیکھک ہو لیکن کتاب چھاپنے کیلئے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور ریاست کے جو کلچرل ادارے ہیں اکاڈمی ہیں یا کیندر کی جو اکیڈمیز ہیں ان کو اس کو اپروچ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں مدد کیجئے۔ کتاب چھاپنے کے لیے۔ اور عام لوگوں میں کتاب پڑھنے کا مزاج پیدا نہیں ہوتا ہے جس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے چھپنے میں جو اس کی پونجی لگی ہے وہ بھی واپس نہیں آتی ہے۔ اس لیے انگلستان یا امریکہ کے ادیبوں کے ساتھ اپنے ملک کے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کتاب کی قیمت چار روپے رکھی جائے تو دو روپے میں بھی ہمارے یہاں لوگ اس کو نہیں خریدیں گے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اگر آپ ادیبوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو صرف کاپی رائٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں اس کا معیار دیکھا جائے اور پھر کتابوں کی خریداری کی ذمہ داری سرکار کی ہونی چاہیے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔

میری رائے میں یہ ایک ذمہ داری بنا دی جائے کہ چاہے کسی بھاشا میں ہوں ان ادیبوں کو جو اچھے لکھنے والے ہیں جن کی اپروچ نہیں ہے جو سرکار تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ان کی کتابوں کو لائبریریز کے لیے خریدا جائے۔

ادیبوں اور لیکھکوں کا خون چوسنا اور ان کی محنت کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنا ہندوستان کے پبلشروں کا ایک دھندا بن چکا ہے۔ ہندوستان کی یہ ٹریجڈی ہے کہ ادیب لکھتا ہے اور کتاب چھپتی ہے لیکن اس کا زیادہ فائدہ پبلیشر کو ہوتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہندوستان پاکستان دونوں دیشوں میں اردو انگریزی اور پنجابی زبانیں رائج ہیں اور ان دونوں

against British imperialism and also against the feudal order that we had till the other day, should be published by the Government of India. It should be published not only in English, not only in Hindi, but in all those languages which have come to be recognised by our Constitution. Today some effort is being made by some State Governments to publish the short biographies in regard to the freedom fighters of their respective States. But all the States have not done this. And then what is more, there is a great need from the All-India platform to publish similar volumes of biographies at least of those people who have played a very prominent role and who have made the greatest possible sacrifice. And a bigger effort should be made by the Government of India.

Secondly, I am also in favour of the Government of India constituting a fund in order to be able to help not only the poets, but also those who write useful textbooks for students at the college as well as at the high school level. To-day, as my hon. friend from Kashmir has said, most of these authors are obliged to go about begging, in order to get enough money to get their books printed. We have to save our authors, and prospective authors also from this kind of a trouble, by having a Trust whose main task would be to encourage budding authors, poets and writers in various languages. The sooner who make an effort in this direction, the better it would be for the nation as a whole.

They have what is known as the Book Trust. It has published quite a large number of good books ; but it is not provided with sufficient money, and it has not been acting as effectively and efficiently as one would have wished. Therefore, I would like our hon. Minister to pay special attention to these two suggestions that have been made by Shri Ramavatar Shastri and our friend from Kashmir.

SHRIMATI SHEILA KAUL : I have already covered most of the points, practically all the points ; but I would like to add that Section 19A takes care of the proper payment of royalty, i.e. a new thing has been added to the Bill. In the Ministry of Education and Culture, there are schemes for helping writers in poverty. There is also a scheme of buying copies of books written by authors. These books, of course, should be of a certain standard. There is a procedure for buying these books. These books are sent to the Ministry ; and they are sent to a Committee. That Committee takes note of all this ; and if it thinks that it is a good book, then copies of that book are purchased. So, there are schemes in the Ministry also.

But most of all, I personally feel that the attitude of the people at large i.e. the public, is important. Why should Prem Chand have suffered ? Now his son is getting royalties ; but during his time, Prem Chand suffered. The same thing happened with Nirala. Why did he suffer ? It is because people of those times did not care for them. It is not only the Government or other agencies but our own people who have also to take interest. We, as people, should take care of these authors. That is what I personally think.

PROF. N.G. RANGA : It is because people are not able to do it, that we expect Government to do it.

SHRIMATI SHEILA KAUL : People must do it.

PROF. N.G. RANGA : If people are far-sighted and sensible enough to do it, there will be no need for Government to do it at all. So, it is the primary duty of the Government in a country like ours. Our people are not in a position to be in the habit of spending money to purchase books, and build up personal libraries. Government should go out of its way to do this.

SHRIMATI SHEILA KAUL : There are Government libraries all over, if you are speaking about libraries. But what I feel is that we must give respect to our authors. Public should show respect to authors. (*Interruption*). It is not a matter for laughing. I feel it is a serious matter : we must take care of the authors. It is for this reason that the Copyright Bill has been brought. Authors must not suffer, and publishers must not suffer. Whenever anything happens, they go to the Copyright Board, which takes care of these things.

We are thinking of looking into the points made by Shri Ramavatar Shastri that there should be some literature on freedom fighters.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The Motion was adopted.

15-40 hrs.

HINDU WIDOWS' RE-MARRIAGE (REPEAL) BILL

MR. CHAIRMAN : We now take up the next item namely, the Hindu Widows' Re-marriage (Repeal) Bill.

Now the Minister.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI GHULAM NABI AZAD) : I beg to move :

> "That the Bill to repeal the Hindu Widows' Re-marriage Act, 1856, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. Chairman, Sir, the object of this Bill is to repeal the Hindu widows Re-marriage Act, 1856 as passed by the Rajya Sabha on 1st August, 1983. As the hon. Members are aware, the Hindu Widows Re-marriage Act was enacted in 1856, thanks to the pioneering efforts of a great social reformer, namely Eshwarchundra Sharum who later came to be known as Ishwarchandra Vidyasagar. This enactment sought to remove all obstacles to the marriage of Hindu widows. It allowed Hindu widows to remarry. It also made certain provisions regarding maintenance, interstate succession and testamentary succession, guardianship and other rights including adoption.

The Act, however, contained provisions purporting to impose on widows certain disabilities, such as, in relation to the right of inheritance of a childless widow. This can hardly be allowed to continue in the present structure of our society. Accordingly, the Law Commission studied this piece of legislation in depth and had submitted to the Government its Eighty First Report in December, 1979, recommending the repeal of this anachronistic piece of legislation.

The Law Commission has referred to the other enactments, such as, the Hindu Marriage Act, 1955, the Hindu Succession Act, 1956, the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, which not only cover the same field as the Hindu Widows Re-marriage Act, 1856 but also made fundamental and radical changes in the personal Law of Hindus, relating to marriage, succession and guardianship, adoption and maintenance. These four Acts supersede any other Law inconsistent with the provisions of those Acts.

The present Bill seeks to implement the recommendation made by the Law Commission for the repeal of the Hindu widows Re-marriage Act, 1856. I commend this measure to the House.

SHRI AMAL DATTA (Diamond Harbour) : Mr. Chairman, this is a one line Bill to repeal an Act of 1856. On the face of it, it is very innocuous. I am not saying that there is any oblique purpose in the Bill itself. But what is the object of bringing forward the Bill now allotting one hour time when the time of Parliament is so precious that is setting out in the objects and reasons appended to the Bill ? It says that "the Law Commission has recommended that the Hindu Widow Re-marriage Act, 1856, having become obsolete, should be repealed so as to foreclose any possible arguments based on the construction of the provisions of this Act and the later Acts." It is to guard against any contingent argument which may sometimes be taken by any lawyer in the court of law. That is why this Bill is being passed by Parliament. Now, this is really, in my very humble opinion, waste of time, because there has not been in the last not 30 years but at least 27 years—since the passage of the several Bills ; four Bills which have been mentioned here—any argument based on this particular Bill which is now sought to be repealed. But that is not all. In